Need to amend Wild Life Protection Act to prevent loss of human lives due to attacks by wild animals

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, there is a need to amend the Wildlife Protection Act to ensure scientific management of forests and wildlife in India. The number of wild animals is increasing and even in cities, loss of lives is being reported on account of wild animal attacks. An elderly person lost his life in Panoor Municipality of Kannur district in a wild boar attack. He was attacked while he was visiting his farm. The killing by elephants is continuing in Aralam. A tribal couple was killed in a wild elephant attack while collecting cashew nuts at Aralam farm. Sir, there is an urgent need to tackle this issue. The prevalent forest and wildlife laws are for protecting the interests of the wild animals, but the protection is happening at the cost of the lives and livelihoods of the tribals and famers living in the high range areas of Kerala and other regions. In many an instance, the remedial measures suggested by the Act are very costly and impractical. There is a need to adopt international standards when dealing with such problems. There is a need to ensure local autonomy and freedom, so that the States could effectively tackle the issue. The Government should take urgent steps in this regard.

Concern over increasing plastic pollution and waste management in the country

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में तेजी से बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और Urban Waste Management की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

भारत हर साल 4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से केवल 25% का ही recycling या treatment किया जाता है, जबकि 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक जल, वायु और भूमि को प्रदूषित कर रहा है। देश भर में 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जलाया जाता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अकेले दिल्ली में प्रतिदिन 3,800 टन ठोस कचरा बिना उपचार के जमा हो रहा है, जिससे नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगस्त, 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीर पर्यावरणीय संकट करार दिया था।

केंद्र सरकार ने "स्वच्छ भारत मिशन" और Single-Use Plastic पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव होगा, जब एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वाले निर्माताओं तथा विक्रेताओं पर कठोर दंड लगाया जाए। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित निरीक्षण को अनिवार्य किया जाए, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को औपचारिक पुनर्चक्रण योजनाओं से जोड़ा जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए, ताकि एक प्रभावी और टिकाऊ कचरा प्रबंधन नीति लागू हो सके। जब तक